जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 356 प्रभात जालोर, शुक्रवार 4 अप्रैल, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

एक ही झटके में ट्रम्प अमेरिका को 17वीं शताब्दी की सोच में ले गये

उस समय की सोच थी, आयात बुरा है, निर्यात अच्छा। अतः अपना सारा सामान निर्यात करो व सोना आयात करो

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। यूक्रेन वॉर की तरह किसी ने नहीं सोचा था कि रूस आक्रमण करने की योजना लागू कर देगा। किसी को भी यकीन नहीं था कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की जो धमकी दे रहे हैं वे उस पर अमल करेंगे पर 2 अप्रैल से वह लागू हो गई। उनकी घोषणा जितनी सोची गई थी वास्तव में उससे भी ज्यादा भयावह है।

डॉनल्ड ट्रंप का 2 अप्रैल का टैरिफ का फैसला, आशंकाओं से ज्यादा बुरा साबित हुआ। एक झटके में ही उन्होंने अमेरिका की व्यापार व्यवथा को 125 साल पीछे धकेल दिया है। नए टैरिफ के साथ अमेरिका 1900 के टैरिफ प्रणाली में पहुँच गया है।

यही नहीं ट्रंप के सोचने का तरीका भी बदल गया है।

दार्शनिक रूप से हमें उस युग में पहुंचा दिया गया, जब अर्थशास्त्री मानते थे कि निर्यात अच्छा है और आयात बुरा। इसलिए सब चीजों का निर्यात करो, सिर्फ गोल्ड का ही आयात करो, 17वीं सदी के दौर में जाने को बाध्य किया जा रहा है।

- **साथ ही, यह भी सच है कि ट्रम्प ने जो नया टैरिफ ऑर्डर पास किया, वह, जो आशंका थी, उससे भी ज्यादा सख्त व हानिकारक निकला, वाणिज्य व व्यापार की दृष्टि से।**
- **भारत से आये सामान पर ट्रम्प ने लगभग 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया और चीन से अमेरिका भेजे गये सामान पर 54 प्रतिशत टैरिफ लगाया है।**
- **चीन पर बढ़ा हुआ टैरिफ ज्यादा दुखदायी इसलिये भी है, क्योंकि चीन की इकॉनमी एक्सपोर्ट पर आधारित है। उदाहरण के लिये, चीन में निर्मित ''स्टील'' का आधा माल ही चीन में खपता है, बाकी एक्सपोर्ट होना जरूरी है चीन की वाणिज्य नीति के अनुसार।**
- **दूसरी ओर, हालांकि, भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगी है, पर, भारत की जीडीपी का 2.2 प्रतिशत हिस्सा ही एक्सपोर्ट होता है। अतः भारत को इस बढ़े हुए टैरिफ का ज्यादा खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा।**
- **पर, कई देश, जिनका वाणिज्य केवल सामान के एक्सपोर्ट पर निर्भर है, जैसे बाँग्लादेश, की इकॉनमी अमेरिका को गारमैंट एक्सपोर्ट पर निर्भर है, पर फिर भी 34 प्रतिशत टैरिफ लगा है और अब तक बाँग्लादेश के सामान पर लगभग ज़ीरो प्रतिशत टैरिफ लगता था। अतः बाँग्लादेश के सामने भारी संकट है।**

वह व्यापारीवाद का सुनहरा युग था, जिस उस दौर के अर्थशास्त्री जीन बैपरिस्ट कोलबर्ट ने पेश किया था। वर्ष 1949 में अर्थशास्त्री सर जॉन क्लैयहम ने कोलबर्ट की किताब की समीक्षा कर उन्हें मूर्ख, तानाशाह व चिड़चिड़ा करार दिया था। यह बात ट्रंप के लिए भी सटीक टिप्पणी लगती है।

एक ही झटके में ट्रंप ने 2 अप्रैल को विश्व व्यापारिक संरचना और आर्थिक संबंधों को नष्ट कर दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतने वर्षों में बड़ी सतर्कता से बनाए गए थे।

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन को समाप्त किया जा सकता है। देशों के बीच व्यापारिक विवाद सुलझाने का संगठन भी पुराना हो गया है। शिकायतें दर्ज करने का कोई मतलब नहीं रहा है। अगर विश्व की सबसे भी ताकतवर अर्थव्यवस्था उन देशों पर भारी टैरिफ लगा सकती है। जहाँ तो सबसे पसंदी राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित नियमानुसार व्यापार प्रणाली कहाँ रह जाती है।

वैश्विक व्यापार व्यवस्था के प्रशंको सादर के रखते है पर सवाल है कि 2 अप्रैल के बाद भारत का क्या होगा, सामान्य रूप से देखें तो गंभीर कुछ भी नहीं, पर, भारत के कुछ संवेदनशील क्षेत्र अवश्य प्रभावित होंगे, पर, आमतौर पर भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर ज़िंदा बम मामले में फैसला आज

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में 13 मई 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में शुक्रवार 4 अप्रैल को फैसला देगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक श्रवण कुमार ने मामले के चार आरोपी शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व सैफुर्रहमान के खिलाफ 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। वहीं करीब 1200 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए।

- **जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर ज़िंदा बम मिले थे।**

बचाव पक्ष ने 122 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपी पक्ष की ओर से अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले और पूर्व में जयपुर बम ब्लास्ट केस के तथ्य समान हैं। इन्हीं समान तथ्यों पर हाईकोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष यह भी पता नहीं कर पाया है कि साइकिल किसने रखी थी। वहीं चांदपोल गेट के बाहर किसी आरोपी की निशानदेही भी साबित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने राज्यसभा में बड़ी जोशीली बहस की वक्फ के विधेयक पर

विपक्ष के नेता ने सरकार पर ट्विटर (अब एक्स) पर आरोप लगाया कि यह विधेयक मुसलमानों को ''मार्जिनाइलाइज़'' करने का प्रयास है, उनके ''पर्सनल लॉज़'' तथा प्रॉपर्टी के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अप्रैल। केन्द्रीय संसदीय मामलात तथा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ने आज इंडिया ब्लॉक के कड़े विरोध के बीच वक्फ अमेन्डमैंट बिल तथा मुसलमान वक्फ (रिपील) बिल विचार करने तथा पारित होने के लिये राज्यसभा में पेश कर दिया।

लोकसभा में 12 घंटे तक चली बहस के बाद, यह बिल देर रात पारित हो गया था। इसके पक्ष में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े थे। इस बिल के विरोध में सभी विपक्षी नेता एकजुट थे, जो आज की बँटी हुई राजनीति में एकजुटता की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना है।

बहस की प्रकृति एवं विषयवस्तु साफ तौर पर दर्शाती है कि कल ''धर्मनिरपेक्ष'' इंडिया ब्लॉक हिन्दुत्व ताकतों से टकराने के लिये कृतसंकल्प नज़र आया। जिनकी पूरी राजनीति हिन्दू-मुस्लिम विभाजन के चारों ओर घूम रही है। जहाँ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ''एक्स'' पर कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक मुस्लिमों को हाशिये पर पहुँचाने वाला, तथा पर्सनल लॉ और सम्पत्ति के अधिकारों को छीनने वाला हथियार एवं साधन है, वहीं, रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ सम्पत्तियों के नियमन एवं प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करना है।

- **पर, संसदीय मामलों के मंत्री रिजीजू ने भी पुरजोर ढंग से विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि विधेयक लाने का मकसद, उन मुद्दों व चुनौतियों का समाधान करना है, जो वक्फ की सम्पत्ति के प्रबंध व संचालन के दौरान सामने आई हैं।**
- **रिजीजू ने यह भी कहा कि यह विधेयक पिछली सरकारों के उन कामों को पूरा कर रहा है, जो अधूरे रह गये थे।**
- **रिजीजू के अनुसार, दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं कि अब यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि कोई सम्पत्ति वक्फ की है, उसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। पहले प्रावधान था कि अगर वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि सम्पत्ति वक्फ बोर्ड की है तो उसे वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित कर दिया जाता था। अब नए विधेयक में यह प्रावधान हटा दिया गया है।**
- **संख्या बल के कारण संभावना यह है कि राज्यसभा में भी यह विधेयक पारित हो जायेगा।**

राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस, भाजपा तथा उसके मित्र दलों द्वारा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बम की धमकी ने जयपुर कलैक्ट्रेट खाली कराया

दो सौ कमरों की बम स्क्वॉड व इमरजेन्सी रैस्पॉन्स टीम द्वारा की गई जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

जयपुर, 3 अप्रैल। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर खाली करवाया गया। जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर धमकी का ईमेल आया था। धमकी वाले ईमेल की जानकारी कलेक्टर ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को दी। इसके बाद आनन-फानन में पूरे परिसर से लोगों को बाहर निकाला गया। करीब दो सौ कमरों की जांच के लिए बम स्क्वॉड और इमरजेंसी रैस्पॉन्स टीम को भी बुलाया गया। हालांकि, सर्च के दौरान किसी भी एजेंसी को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बड़ी संख्या में पुलिस के मौजूद रहने के साथ ही, कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों के बाहर निकलने से कलेक्ट्रेट के आस-पास जाम के हालात हो गए। वाहनों की लम्बी कतारें लग गईं। पुलिस की जांच खत्म होने के बाद ही यातायात सामान्य हो पाया।

- **बड़ी संख्या में पुलिस तथा कलैक्ट्रेट के सारे कर्मचारियों के बाहर होने के कारण पूरे क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी।**
- **धमकी का ई-मेल कलैक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी की सरकारी आईडी पर आया।**

जानकारी के अनुसार, सभी कर्मचारी अपने समय के अनुसार जयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए थे। सुबह सामान्य दिनों की तरह कामकाज चल रहा था। अचानक 11.30 बजे के आसपास शोर मचने लगा। सभी को परिसर खाली करने के लिए कहा गया। इसी के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अंदर पहुंचने लगे थे। जब कर्मचारी बाहर निकले तो पता चला कि कलेक्टर के पास बम की धमकी का ईमेल आया है। दोपहर 2 बजे तक भी बिल्डिंग परिसर में बम स्क्वॉड की टीमें मौजूद थीं।

पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि जयपुर कलेक्टर ऑफिस के मेल आईडी पर यह मेल आया कि ''2-जी मामले में सवुक्कु शंकर के साथ हुए अनुचित व्यवहार और सादिक बलवा की हिरासत में हुई मौत का बदला लेने के लिए बम रखा गया है। हम सुरक्षा एजेंसी को भगवान के नाम पर रैस्क्यू ऑपरेशन चलाने का चैलेंज देते हैं। बम वीकेंड पर पहले से ही आज के लिए लगा दिया गया था, जो अन्ना यूनिवर्सिटी एमआईटी कैंपस के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तैयार किया गया है। आज इस बम से धमाका करेंगे। हमारा लक्ष्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान से ड्रोन से आई ढाई करोड़ की हेरोइन जब्त

श्रीगंगानगर, 3 अप्रैल (निसं) जिले के श्रीकरणपुर बॉर्डर पर बीएसएफ (बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स) ने पाकिस्तान से आई हेरोइन की भारी खेप जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 11 एफ गांव में रात साढ़े 11 से 12 बजे के बीच वहाँ ड्रोन की गतिविधि देखी गई। बीएसएफ जवानों ने तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचना दी। एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय करने पर ड्रोन वापस नहीं जा सका और वहीं गिर गया। ड्रोन से 500 ग्राम हेरोइन गिराई गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत ढाई करोड़ रुपए आंकी गई है।

- **श्रीकरणपुर बॉर्डर पर बीएसएफ ने देर रात हेरोइन का पैकेट व ड्रोन बरामद किया।**

बीएसएफ ने श्रीकरणपुर पुलिस को सूचना दी। सीओ संजीव चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान में एक पीले रंग का हेरोइन का पैकेट और ड्रोन बरामद किया गया। सुबह भी बीएसएफ और पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था, लेकिन इसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डी.एम.के. वक्फ बोर्ड विधेयक को न्यायालय में चुनौती देगा

अगले वर्ष तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्टालिन अपने मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में संगठित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। सैक्युलर ब्लॉक में खड़ा आखिरी आदमी, जो केन्द्र सरकार और भाजपा से मुकाबला कर रहा है, वे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। दोबारा चुनाव जीतने के लिए वे इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं।

अब उन्होंने वक्फ बिल पर अपने आक्रामक रुख से नई गुगली उछाली है कि वे वक्फ बिल को कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने इस बारे में तमिलनाडु विधानसभा में घोषणा की।

स्टालिन और द्रमुक पहले राजनेता एवं राजनैतिक दल हैं, जिन्होंने विवादास्पद वक्फ संशोधन का खुले आम विरोध किया है,वो भी राज्य विधानसभा में। वक्फ बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा।

- **इससे पहले, चुनाव की तैयारी के तहत ही शायद, स्टालिन कई जज़्बाती मुद्दों को, जैसे नई शिक्षा नीति, डीलिमिटेशन और काचातीवू द्वीप के मामले पर जमकर बोलते रहे हैं।**

द्रमुक ने संसद के भीतर और बाहर भी वक्फ बिल का विरोध किया। मुख्यमंत्री खुद वक्फ बिल के विरोध में उतर आए हैं और वे इसे एक चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, जो राज्य में अल्पसंख्यक मतों को द्रमुक के पक्ष में एकजुट कर देगा। वे पहले ही तीन भावनात्मक मुद्दे उठा चुके हैं - परिसीमन, भाषा और काचातीवू द्वीप और अब इसमें वक्फ बिल के आ जाने से उनका पलड़ा भारी हो रहा है।

इस स्थिति ने अन्नाद्रमुक को मुश्किल में डाल दिया है, जो विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की तैयारी में है। यद्यपि यह गठबंधन भाजपा को भारी लाभ पहुंचा सकता है, पर अन्नाद्रमुक को और ज्यादा कमज़ोर कर सकता है। अन्नामलाई के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की ताकत बढ़ी है। पर इससे अन्नाद्रमुक कमज़ोर हुई है। यही नहीं, भाजपा ने अपने कठपुतली नेताओं के जरिए अन्नाद्रमुक को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया है। अटकलें थीं कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री व अन्नाद्रमुक से अलग हुए गुट के नेता ओ पन्नीरसेल्वम का समर्थन किया था। भाजपा की कोशिश है कि दोनों गुट एक हो जाएं।

पर लम्बी कानूनी व राजनैतिक लड़ाई के बाद ओ पन्नीरसेल्वम को निकाल पाने में सफल रहने के बाद, अन्नाद्रमुक के वर्तमान अध्यक्ष ई. पलानीस्वामी उन्हें वापस लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने पन्नीरसेल्वम को वापस लेने से मना कर दिया, यही नहीं लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने भाजपा से सम्बंध तोड़ दिया था।

पर विपक्ष के वोट बंटने से लोकसभा चुनाव में द्रमुक को एकतरफा जीत मिली। इसलिए एक बार फिर अन्नाद्रमुक और भाजपा गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। पर स्टालिन एक के बाद एक गुगली फेंक रहे हैं और इस बार उन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई की घोषणा कर अन्नाद्रमुक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अन्नाद्रमुक का भाजपा के साथ नज़र आना उसके अल्पसंख्यक वोट को प्रभावित कर सकता है। तमिलनाडु में 6 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है और वह एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है।

खंडवा में कुएं में जहरीली गैस से 8 मरे

खंडवा, 03 अप्रैल। खंडवा में एक कुएं में जहरीली गैस से दम घुटने के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 8 शव कुएं से बाहर निकाल लिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस, प्रशासन और एसडीईआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।

- **गणगौर विसर्जन के लिए कुएं की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ।**

ये घटना गुरुवार शाम को जिले के छैगांवमाखन क्षेत्र के कोंडावत गांव की है। बताया जा रहा है कि गणगौर विसर्जन को लेकर अर्जुन नाम का शख्स कुएं की सफाई करने उतरा, जो जहरीली गैस के कारण बेसुध होकर कुएं में जमे दलदल में डूब गया। उसे बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 7 और लोग कुएं में उतरे। ये सब भी जहरीली गैस के कारण दम घुटने से डूब गए और इनकी मौत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अमेरिका छींकता है, तो विश्व को ज़ुकाम हो जाता है'

अमेरिका ने बेरहमी से सभी देशों पर, नया टैरिफ लागू किया, 2 अप्रैल से

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। संपूर्ण विश्व एक बार फिर हिल गया, जब सदियों पुरानी यह कहावत सच साबित हुई कि ''जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है।'' इस बार यह छींक फुसफुसाहट नहीं, बल्कि आसमान से गिरी बिजली की गरज के रुप में आई है- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की, रैसिप्रोकल टैरिफ (प्रत्युत्तर शुल्क) लगाने की घोषणा ने विश्व के बाज़ारों को हिला दिया। ट्रंप ने एक ही झटके में एक आर्थिक तूफान खड़ा कर दिया और कसम खाई कि वे, अपने व्यापारिक साझेदारों द्वारा अमेरिका से लिए जाने वाले टैरिफ का लगभग आधा टैरिफ लगाएंगे।

सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है भारत, जो अमेरिका को किए जाने वाले अपने निर्यात पर 26 प्रतिशत टैरिफ का सामना कर रहा है। यह कदम ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके द्वारा वे अमेरिकी टैरिफ को अन्य देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ के समानांतर बनाना चाहते हैं। इसका लक्ष्य है, अमेरिका की दृष्टि से एक न्यायसंगत व्यापारिक परिदृश्य तैयार करना। भारत, जिसने वर्षों से अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक साझेदारी बनाकर रखी है, को अब अपने प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर गंभीर दबाव का सामना करना पड़ेगा।

बुधवार को वाइट हाउस के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, ''भारत बहुत, बहुत सख़्त है, बहुत, बहुत सख़्त है। प्रधानमंत्री अभी-अभी गए हैं, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन, आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) वसूलते हैं।''

तथापि, मोदी के साथ उनके ''अच्छे व्यक्तिगत संबंधों'' ने उन्हें भारत पर उच्च शुल्क लगाने से नहीं रोका।

ट्रंप के इस कदम पर भारत की अधिकारिक प्रतिक्रिया संयमित रही। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ''इसका मिलाजुला असर होगा, यह भारत के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है।'' जबकि, निर्यातकों को इस बात से सांत्वना मिली कि यह शुल्क भारत के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

- **अमेरिका की नई टैरिफ रणनीति है, जो देश अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाते हैं, उसका आधा टैरिफ अमेरिका उन देशों से अमेरिका निर्यात किये गये सामान पर लगायेगा।**
- **उदाहरण के लिये, वियतनाम पर 46 प्रतिशत, ताईवान पर 32 प्रतिशत, जापान पर 24 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत, थाईलैण्ड पर 36 प्रतिशत लगायेगा अमेरिका।**
- **यूरोप पर भी 20 प्रतिशत टैरिफ लगेगा तथा यूरोपीय देश अपनी आर्थिक व वाणिज्य रणनीति तैयार कर रहे हैं, टैरिफ से उत्पन्न संकट का सामना करने के लिये।**
- **ट्रम्प का कहना है, भारत, अमेरिकी सामान पर 52 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। अतः अमेरिका अब भारतीय माल पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा।**
- **चीन अमेरिकी सामान पर 67 प्रतिशत टैरिफ लगाता है। अतः चीन में निर्मित सामान पर अमेरिका 34 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा।**

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि चीन अमेरिकी माल पर 67 प्रतिशत टैरिफ लगाता है तो प्रतिक्रिया में अमेरिका चीनी माल पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा।

कुछ ही दिन पहले, यू.एस. ट्रेड रिप्रैज़ैन्टेटिव (यू.एस.टी.आर.) ने 2025 की नैशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट (एन.टी.ई.) जारी की, जिसमें कहा गया है कि भारत, कृषि उत्पादों, दवा उत्पादन और मादक पेय पदार्थों जैसी अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाता है, इसके अलावा गैर टैरिफ बाधाएं भी लगाता है।''

अमेरिका की टैरिफ रणनीति केवल भारत को ही प्रभावित नहीं करती है। वियतनाम (46 प्रतिशत), ताईवान (32 प्रतिशत), जापान (24 प्रतिशत), दक्षिण कोरिया (25 प्रतिशत) और थाईलैण्ड (36 प्रतिशत) जैसे देश भी इसके परिणाम का आकलन कर रहे हैं। बीस प्रतिशत टैरिफ के साथ यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव की संभावना से अपनी आर्थिक रणनीतियों का पूनर्मूल्यांकन का रहा है।

भारत पर लगाया गया इस स्तर का शुल्क, दोनों देशों के बीच बड़ी मेहनत से बनाए गए व्यापार संबंधों पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करेगा। अमेरिका के साथ मजबूत व्यापार साझेदारी का आनंद ले रहा भारत, अब इस चुनौती का सामना कर रहा है कि उसके प्रमुख निर्यात क्षेत्र उच्च लागत और अमेरिकी बाज़ारों में घटती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित होंगे। भारत का आई.टी. सैक्टर, जिसमें टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेज़ (टी.सी.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वनरक्षक भर्ती, फरार आरोपी पर 50 हजार का ईनाम घोषित

जयपुर, 3 अप्रैल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में वांछित फरार बदमाश जबराराम जाट पर 50 हजार रुपए इनाम की घोषणा की है। आरोपी बाड़मेर में ग्रेड थर्ड टीचर के पद पर कार्यरत है और वन रक्षक भर्ती मामले में फरार चल रहा है। एसओजी की ओर से उसे पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

- **आरोपी जबराराम बाड़मेर में थर्ड ग्रेड टीचर है और अभी तक पकड़ में नहीं आया है।**

एडीजी (एसओजी व एटीएस) वी.के. सिंह ने बताया कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में साल-2024 में बांसवाड़ा के राजतलाब थाने में मामला दर्ज हुआ था। वन रक्षक भर्ती मामले की जांच में जबराराम जाट निवासी कालवा पचपदरा बालोतरा भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)